ब्रिटेन में जनगणना समाप्त करने पर विचार

यूनाइटेड किंगडम में हर दस साल में जनगणना का सिलसिला 1801 में शुरू हुआ था। इस कड़ी का आखरी सर्वेक्षण 2011 में हुआ था। मगर अब शोधकर्ताओं से पूछा जा रहा है कि क्या इस सिलसिले को जारी रखा जाए।

हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने सलाह-मशविरे की एक प्रक्रिया शुरू की है जो संभवतः ब्रिटेन की जनगणना प्रणाली में आमूल परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेगी। इससे न सिर्फ सर्वेक्षण की विधि बल्कि उसमें शामिल आबादी, सर्वेक्षण की आवृत्ति वगैरह पर भी असर पड़ेगा।

एक प्रस्ताव यह है कि जनगणना के आंकड़े प्राप्त करने के लिए मूलतः नेशनल डेटाबेसों का उपयोग किया जाएगा और इसमें कुछ जानकारियां जोड़ने के लिए कुछ छोटे-छोटे सर्वेक्षण कर लिए जाएंगे। इन सर्वेक्षणों का स्वरूप नमूना-आधारित होगा और हर साल करीब 4 प्रतिशत जनसंख्या को ही शामिल किया जाएगा।

दूसरा विकल्प जिस पर विचार किया जा रहा है वह यह है कि सांख्यिकी कार्यालय हर दस साल में एक बार हरेक परिवार को एक अनिवार्य प्रश्नावली भेजेगा - पारंपरिक रूप से यही किया जाता रहा है। यह मोटे तौर पर जनगणना जैसा ही होगा मगर इसे ऑनलाइन किया जाएगा। इसे करने में 1 अरब डॉलर का खर्चा आएगा।

जहां तक पहले विकल्प का सवाल है, इसमें प्रति वर्ष 4 प्रतिशत की दर से 10 सालों में आधी से कम आबादी शामिल होगी। इससे प्राप्त आंकड़े उतने गहन नहीं होंगे मगर इसमें खर्च सिर्फ 600 करोड़ डॉलर का होगा।

तो चुनाव यह करना है कि दस साल में एक बार विस्तृत व गहन आंकड़े प्राप्त किए जाएं या हर साल थोड़े-थोड़े तथा कम गहन आंकड़े हासिल किए जाएं। कई जनांकिकी विशेषज्ञों को लगता है कि वार्षिक रूप से किया जाने वाला सतही सर्वेक्षण ज़रूरी जानकारी नहीं दे पाएगा। खास तौर से निवेश वगैरह की प्राथमिकताएं तय करने के लिए काफी गहराई से विस्तृत आंकड़े इकट्ठे करना ज़रूरी होता है। इसके लिए नमूना आधारित सर्वेक्षणों से बात नहीं बनेगी। ***(स्रोत फीचर्स)***